

स्मार्ट सिटी के काम में तेज़ी दिखाएँ विभाग : मुख्यमंत्री

सलीम सैफ़ी की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 12 सितंबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत किए जा रहे निर्माण कार्यों की गति में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री के सख्त रवैये के बाद लोक निर्माण विभाग ने मिशन मोड में निर्माण कार्य कर गति प्रदान की है।

इसी क्रम में राजपुर क्षेत्र के विधायक खजान दास ने आज शहर के विभिन्न स्थानों में निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि तत्काल प्रभाव से सड़कों को ठीक करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। जनप्रतिनिधियों से मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने कार्यदायी संस्था से काम वापस लेकर लोक निर्माण विभाग को यह काम सौंप दिए थे। लोक निर्माण विभाग ने सड़कों के सुधारीकरण कार्य को प्राथमिकता देते हुए काम शुरू कर दिया है।

विधायक खजानदास ने लोनिवि द्वारा



शुरू किए गए कार्यों का लैंसडाउन चौक, नैनीज बेकरी चौक आदि क्षेत्रों में अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को उचित निर्देश दिए। इस दौरान खजान दास ने निर्माण कार्यों में तेजी

लाए जाने के लिए सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर आभार जताया। उन्होंने जनमानस को आश्वस्त करते हुये कहा कि शीघ्र ही दूनवासियों को दून के सड़कों की स्थिति में सुधार देखने को

मिलेगा। इस अवसर पर स्मार्ट सिटी के एजीएम जगमोहन सिंह चौहान, अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग डीसी नौटियाल अपने अधीनस्थ अधिकारियों सहित उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने दिये आपदा ग्रस्त क्षेत्रों का विस्तृत विवरण तैयार करने के निर्देश



न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 12 सितंबर। आपदा प्रभावित गांवों के पुनर्वास तथा भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के स्थायी ड्रीटमेंट के लिये राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय स्तर के कन्सलटेंट की मदद लेने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य में आपदा की स्थिति, आपदा तथा भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान तथा पुनर्वास आदि की

समीक्षा की। इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. सन्धु, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री राधा रतूड़ी तथा सचिव आपदा प्रबंधन डॉ. रंजीत सिन्हा उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि सभी जनपदों की आपदा की स्थिति का पूरा विवरण तैयार किया जाय। जिन गांवों को आपदा से खतरा होने की संभावना है उनके पुनर्वास की भी

योजना तैयार की जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि नैनीताल के बलिया नाला, पिथौरागढ़ की एल धारा सहित अन्य स्थलों के स्थायी उपचार आदि के संबंध में भी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के कन्सलटेंट की सेवायें लिये जाने पर ध्यान दिया जाय ताकि आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास एवं भूस्खलन प्रभावित स्थलों एवं क्षेत्रों का प्रभावी ड्रीटमेंट की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके

बुंदी में फंसे यात्रियों को हेलीकॉप्टर से किया रेस्क्यू, ग्रामीणों समेत 46 लोगों को लाए धारचूला

धारचूला (पिथौरागढ़) 12 सितंबर। तवाघाट-लिपुलेख सड़क बंद होने के कारण चार दिनों से बुंदी गांव में फंसे 27 आदि कैलाश यात्रियों को सोमवार को हेलीकॉप्टर से धारचूला लाया गया। आठ उड़ानों में ग्रामीणों सहित 46 लोगों को लाया गया।

तवाघाट-लिपुलेख सड़क के मलघाट में चार दिनों से सड़क बंद है। 19वें दल के 27 यात्री ओम पर्वत और आदि कैलाश की यात्रा करने के बाद बुंदी में फंसे थे। मौसम ठीक होने पर प्रशासन ने सोमवार को हेलीकॉप्टर से पहुंचाया।

बारिश का कहर: कपकोट में अतिवृष्टि ने मचाई तबाही, स्कूल और खेत खलिहान मलबे से पटे, कई मकान खतरे की जद में हेली से 27 यात्री, चार बीमार महिलाओं सहित 46 लोगों को धारचूला लाया गया।

गुजरात, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र निवासी यात्रियों ने धारचूला पहुंचने पर राहत महसूस की। आदि कैलाश यात्री दीपिका, लोमेश भलावत और दिल्ली की यात्री शोभना ने स्थानीय प्रशासन का आभार जताया।

तीन दोस्तों की दर्दनाक मौत, गदरे में मिले शव

चेहरा देख मची चीख पुकार, दो थे घर के इकलौते चिराग

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

कोटद्वार, 12 सितंबर। तीन दिन पहले लापता हुए तीन बच्चों की तलाश में जुटे परिवारों की आखिरी उम्मीद भी तब टूट गई जब सोमवार को तीनों के शव पौड़ी हाईवे के पास टूट गदरे में बरामद हुए। तीन दिन से वे हर पल बच्चों के सही सलामत होने की प्रार्थना कर रहे थे। सोमवार सुबह गदरे में तीन शव मिलने की सूचना मिलते ही वे घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। बच्चों का चेहरा देखते वहां चीख पुकार मच गई। आर्यन और रौनक परिवार के इकलौते बेटे थे।

गोविंद नगर निवासी वीरेंद्र ने बताया कि उनका बेटा आर्यन (16) पुत्र वीरेंद्र और पड़ोस में रहने वाले उसके दो साथी नमो (13) पुत्र संजीव कुमार और रौनक (13) पुत्र कृष्ण अच्छे दोस्त थे। तीनों स्कूल की पढ़ाई के बाद ज्यादातर समय साथ में खेलते थे।

आर्यन नौवीं, रौनक छठी और नमो सातवीं कक्षा में पढ़ता था। तीनों अक्सर सुबह घूमने के लिए सिद्धबली की ओर जाते थे और कभी-कभी स्कूटी भी ले जाते थे। तीनों एक घंटे में ही लौटकर आ जाते थे। शुक्रवार सुबह वे तीन घंटे बाद भी नहीं लौटे तो परिजन चिंतित हो गए।

बच्चों की तलाश में दोपहर से शाम हो गई लेकिन उनका पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस को बच्चों के लापता होने की सूचना दी गई। बच्चों की चिंता में तीनों घरों में शुक्रवार से चूल्हा नहीं जला था। सोमवार सुबह तीनों के शव मिलने के बाद गोविंद नगर मातम में डूब गया। क्षत विक्षत होने के कारण शव को घर नहीं ले जाया गया।



परिजनों को गाड़ीघाट स्थित पोस्टमार्टम हाउस में ही अंतिम दर्शन के लिए बुलाया गया। बच्चों के चेहरे देख वहां चीखपुकार मच गई।

गोविंदनगर की पार्षद कविता मित्तल, संजय मित्तल, प्रवेश रावत और अरविंद वर्मा ने बताया कि बच्चों के शव मिलने की सूचना से पूरे इलाके में मातम पसर गया। परिजन घटना को संदिग्ध मानकर चल रहे हैं। लोगों ने भी मामले में गहराई से जांच की मांग की है।

आर्यन के पिता वीरेंद्र ने बताया कि कि उनका बेटा काशीरामपुर तल्ला के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। कुछ दिन पूर्व लकड़ी पड़ाव के कुछ युवकों ने उनके बेटे के साथ मारपीट की थी। तब स्कूल के प्रधानाचार्य ने आर्यन को किशोरों के इरादे ठीक नहीं होने की बात कहते हुए उनसे न उलझने की सलाह दी थी।

वीरेंद्र ने बताया कि तीनों बच्चे रोजाना सुबह स्कूटी से सिद्धबली मंदिर तक जाते थे और एक घंटे में लौट आते थे। इससे पहले उन्होंने कभी देर नहीं लगाई। पुलिस का कहना है कि मामले में हर पहलू को ध्यान रखते हुए जांच की जा रही है।

सेहत : जरूरत से ज्यादा पेनकिलर्स है जानलेवा

महविश की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

आप और हम अक्सर दर्द में बिना किसी सही सलाह के दर्द से राहत के लिए गोलियां खा लेते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर मामले में डॉक्टर के पास जाने के सबसे आम कारणों में से ये एक है। जब व्यक्ति दर्द में होता है, तो डॉक्टर उन्हें पेनकिलर देते हैं। ऐसी कई अलग-अलग दवाएं हैं जो दर्द को कम कर सकती हैं। लेकिन यह देखने में आता है कि बाद में व्यक्ति जरा सा भी दर्द होने पर इन पेनकिलर का सेवन करना शुरू कर देता है।

वास्तव में, उनकी पेनकिलर के प्रति डिपेंडेंसी बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसे पेनकिलर के एडिक्शन के रूप में भी जाना जाता है। पेनकिलर के प्रति डिपेंडेंसी सेहत के लिए हानिकारक होती है। इससे आपको कई तरह के साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, ऐसे कई तरीके हैं, जिनकी मदद से आप पेनकिलर के प्रति डिपेंडेंसी

को कम कर सकते हैं।

पेनकिलर्स के साइड इफेक्ट्स यूं तो पेनकिलर्स का सेवन करने से व्यक्ति को दर्द में राहत मिलती है, लेकिन फिर भी लंबे समय तक अगर इन्हें लिया जाए, तो यह शरीर के विभिन्न भागों और अंगों को प्रभावित कर सकते हैं। दर्द निवारक दवाओं के सेवन से व्यक्ति को कई दुष्प्रभाव नजर आ सकते हैं। जैसे-

- कब्ज की समस्या
- चक्कर आना
- खुजली होना
- बहुत ज्यादा पसीना आना
- जी मिचलाना
- उल्टी का अहसास होना
- किडनी की हेल्थ पर असर
- लिवर के स्वास्थ्य पर प्रभाव
- गट संबंधी समस्याएं
- डिप्रेशन
- चिंता
- हार्ट रेट का बढ़ना
- व्यवहार संबंधी मुद्दे



**पेन किलर
खाने के
नुकसान**

ब्रिटेन के नए किंग के बारे में रोचक जानकारी पढ़ें



न्यूज़ वायरस नेटवर्क

प्रिंस चार्ल्स सबसे लंबे समय बाद ब्रिटिश सिंहासन को पाने वाले उत्तराधिकारी हैं, जिन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स के रूप में 63 साल बिताए थे। 73 वर्ष की उम्र में प्रिंस चार्ल्स राजा बनने वाले सबसे पुराने उत्तराधिकारी हैं। अपनी मां महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद किंग चार्ल्स III बनें। किंग चार्ल्स III ने 9 सितंबर 2022 शुक्रवार को अपने राष्ट्र को संबोधित किया और अपनी मां महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की प्रधानमंत्री लिज ट्रास से भी मुलाकात की।

स्कॉटलैंड के बाल्मोरल कैसल से आते ही बकिंगहम पैलेस के बाहर उमड़ी भीड़ ने उनका स्वागत किया। राजा बनने से पहले प्रिंस चार्ल्स ने 1970 में कैम्ब्रिज में ट्रिनिटी कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। जिसके बाद उन्होंने एक सैन्य कैरियर शुरू किया। जिसमें उन्होंने एचएमएस ब्रोनिंगटन माइनस्वीपर की कमान संभाली। उन्होंने डायना स्पेंसर से शादी की, जो तब 20 साल की थीं। प्रिंसेस डायना बेहद लोकप्रिय थीं। चार्ल्स और प्रिंसेस डायना का 1996 में तलाक हो गया। डायना की 1997 में एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। 9 अप्रैल, 2005 को, चार्ल्स और कैमिला ने शादी की। जिसमें रानी एलिजाबेथ और बेटे



फिलिप मौजूद नहीं थे, लेकिन बाद में सेंट जॉर्ज चैपल, विंडसर कैसल में आशीर्वाद में शामिल हुए।

उन्हें किंग चार्ल्स III के नाम से जाना जाएगा। यह नए राजा के शासन का पहला निर्णय था। वो अपने चार नामों में से किसी एक को चुन सकते थे - चार्ल्स फिलिप

आर्थर जॉर्ज। बता दें कि वो अकेला नहीं है जिसे अपने नाम में बदलाव का सामना करना पड़ा। प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी कैथरीन को अब ड्यूक एंड डचेस ऑफ कॉर्नवाल और कैम्ब्रिज की उपाधि दी गई है, और राजा ने उन्हें प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ वेल्स की उपाधि से सम्मानित किया है।

सावधान! सीट बेल्ट नहीं लगाया तो एयरबैग भी नहीं बचाएंगे आपकी जान

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट 13 सितम्बर, हाल ही में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन सायरस मिस्त्री की मौत एक कार दुर्घटना में हो गई। जानकारी के अनुसार, सायरस जिस कार में सफर कर रहे थे वह काफी तेज रफ्तार से चल रही थी और उन्होंने सीट बेल्ट भी नहीं लगाया था। इस घटना के बाद सरकार ने नियमों में तुरंत सुधार करते हुए कार में बैठने वाले हर व्यक्ति को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि, अब हर तरफ सीट बेल्ट और एयरबैग की चर्चा शुरू हो गई है। तो चलिए जानते हैं दुर्घटना के समय सीट बेल्ट और एयरबैग आपके लिए कितना जरूरी है।

क्यों जरूरी है सीट बेल्ट ?

सीट बेल्ट कार में मिलने वाला एक बेसिक सेफ्टी फीचर है। यह दुर्घटना के समय आपको सीट से बांधे रख आपकी जान बचा सकता है। केवल सीट बेल्ट न लगाने के वजह से हर साल हजारों कार सवार दुर्घटना में अपनी जान गंवा देते हैं। भारत में कार के सामने की सीट पर बैठने वाले लोगों के लिए सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना अनिवार्य था लेकिन पीछे बैठने वाले लोगों के लिए इस तरह को कोई सख्त कानून नहीं था। इस वजह से कार में पीछे बैठने वाले लोग सीट बेल्ट को नजरअंदाज करते हैं और यह दुर्घटना के दौरान काफी घातक साबित होता है। दुर्घटना के समय कार के अंदर बैठे लोगों को आगे की तरफ काफी तेज झटका लगता है जिससे सर, छाती और कंधों पर गहरी चोट लग सकती है। आगे के तरफ झटका लगने से कार चालक का सर



डैशबोर्ड या स्टीयरिंग से टकरा सकता है। सीट बेल्ट दुर्घटना के समय यात्रियों को सीट से बांधे रखता है जिससे सर और शरीर के अन्य हिस्सों के कार से टकराने की गुंजाइश काफी हद तक कम हो जाती है।



विश्वविद्यालय में रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति से भरने के निर्देश : धन सिंह रावत

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 12 सितंबर। सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय सेलाकुई देहरादून का निरीक्षण कर समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने माह नवम्बर तक विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आयोजित करने, लम्बे समय से रिक्त चल रहे शिक्षणोत्तर कार्मिकों के पदों को स्थाई नियुक्ति होने तक प्रतिनियुक्ति/सेवास्थानांतरण के माध्यम से भरने तथा मेडिकल छात्रों को भविष्य में डिजी लॉकर के माध्यम से डिग्रियां उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

मेडिकल यूनिवर्सिटी सेलाकुई के निरीक्षण के उपरांत विभागीय मंत्री ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक में विश्वविद्यालय की बाउंड्रीवॉल का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने तथा कुलपति आवास सहित कुलसचिव एवं अन्य सभी अधिकारियों एवं कार्मिकों के लिये आवास निर्माण की डीपीआर तैयार कर शीघ्र शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिये। उन्होंने विश्वविद्यालय में प्रशासनिक, लेखा एवं मिनिस्ट्रियल संवर्ग के वर्षों से रिक्त चल रहे सभी पदों पर स्थाई नियुक्ति होने तक सेवा स्थानांतरण/

प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के निर्देश विश्वविद्यालय प्रशासन को दिये।

डॉ0 रावत ने कहा कि विश्वविद्यालयों को प्रत्येक वर्ष दीक्षांत समारोह का आयोजन कर डिग्रियां प्रदान करने के निर्देश पूर्व से ही दिये गये हैं। इसी क्रम में मेडिकल विश्वविद्यालय को आगामी नवम्बर माह तक दीक्षांत समारोह आयोजित करने तथा मेडिकल छात्र-छात्राओं को भविष्य में डिजी लॉकर के माध्यम से अंक प्रमाण पत्र सहित अन्य शैक्षिक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने को कहा गया है। विश्वविद्यालय के नये परिसर में निर्माणाधीन बाउंड्रीवॉल सहित अन्य आवश्यक निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने निर्देश भी दिये। विश्वविद्यालय अधिकारियों ने विभागीय मंत्री के परिसर में आगमन पर पुष्पगुच्छ एवं स्मृतिचिह्न देकर जोरदार स्वागत किया। इससे पूर्व डॉ0 रावत ने विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व0 हेमवती नंदन बहुगुणा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया।

इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो0 हेमचंद्र पाण्डेय, कुलसचिव डॉ0 एम0के0 पंत, परीक्षा नियंत्रक प्रो0 विजय जुयाल, वित्त नियंत्रक खजान चंद पाण्डेय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।



जनसुनवाई में प्राप्त हो रही शिकायतों को प्राथमिकता से निस्तारण हो : डीएम



फ़िरोज़ आलम गाँधी की रिपोर्ट न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 12 सितंबर। जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में जनसुनवाई कार्यक्रम में 66 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जनसुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने वचुंअल माध्यम से जुड़े समस्त उप जिलाधिकारी एवं बैठक में उपस्थित संबंधित विभागों के अधिकारियों को जनमानस की समस्याएं अपने स्तर पर निस्तारण करने के निर्देश दिए ताकि जनमानस को अपनी शिकायतों/समस्याओं के निस्तारण हेतु अनावश्यक न भटकना पड़े। साथ ही विभिन्न विभागों से संबंधित समाचार पत्रों एवं विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का स्वतः सज्ञान लेते हुए निस्तारण करना सुनिश्चित करें। जनसुनवाई में व्हीलचेयर पर पहुंचे एक दिव्यांग फरयादी द्वारा अपने किरायेदार द्वारा किराया न देने तथा धमकाने संबंधी शिकायत पर जिलाधिकारी ने नगर मजिस्ट्रेट को आवश्यक कार्यवाही करते हुए संबंधित की शिकायत निस्तारण कराने के निर्देश दिए

वहीं एक फरयादी द्वारा राशन कार्ड स्थानान्तरण न होने की समस्या/शिकायत पर जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को समस्या निस्तारण के निर्देश दिए, जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में मौके पर से ही फरयादी का राशन कार्ड स्थानान्तरण की कार्यवाही की गई।

जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो शिकायत एक बार जनसुनवाई में आ गई है, उसका समयावधि में निस्तारण करें तथा संबंधित को भी सूचित करें यदि किसी शिकायत के निस्तारण में समय लग रहा है तो इसकी सूचना शिकायतकर्ता को भी दी जाए। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त हो रही शिकायतों को प्राथमिकता से निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

आज आयोजित जनसुनवाई में मुख्यतः सड़क क्षतिग्रस्त, अवैध निर्माण, भूमि का सीमांकन कराने, कृषि भूमि पर सुरक्षा दीवार, सम्पत्ति विवाद, आर्थिक सहायता, सेवायोजित करने, स्कूल में दाखिला दिलाने, सीवर खुले में बहने, सड़क घेरकर बनाए जा रैम्प हटाने, परिजनों द्वारा

घर बेचने का प्रयास, शस्त्र लाइसेंस, आदि शिकायतें प्राप्त हुईं। जनसुनवाई में जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग को झुलती तार व्यवस्थित कराने, शिक्षा विभाग को स्कूल में जर्जर भवनों को चिन्हित कर मरम्मत हेतु प्रस्ताव बनाने, सीएमओ को मसूरी में पोस्टमार्टम हाउस, सीएचसी, पीएचसी में कक्ष रैम्प आदि आवश्यक प्रस्तावित करने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) के.के. मिश्रा, नगर मजिस्ट्रेट कुश्म चैहान, उप जिलाधिकारी सदर नरेश चन्द्र दुर्गापाल, प्रशिक्षु आई ए.एस वरुणा अग्रवाल, अपर नगर मजिस्ट्रेट मायादत्त जोशी, जिला पंचायतीराज अधिकारी एमएम खान, जिला पूर्ति अधिकारी विपिन कुमार, अधि0अधि0 डी.सी नौटियाल, स्वास्थ्य, नगर निगम, एमडीडीए, समाज कल्याण, खेल, शिक्षा सहित संबंधित सभी विभागों के अधिकारी/कार्मिक उपस्थित रहे तथा एसडीएम डोईवाला, ऋषिकेश, विकासनगर, चकराता वचुंअल माध्यम से जुड़े रहे।

अक्टूबर में उत्तराखंड आएंगे अखिलेश यादव पार्टी नेताओं में जोश

आलम गाँधी की रिपोर्ट न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 12 सितंबर। उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी जल्द होगा कार्यकारिणी का गठन करेगी। आपको बता दें कि बीते दिनों सपा ने शंभू प्रसाद पोखरियाल को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। वहीं सत्यनारायण सचान को राष्ट्रीय सचिव बनाकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। सपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष शंभू प्रसाद पोखरियाल का कहना है कि एक महीने के भीतर नई कार्यकारिणी का गठन कर लिया जाएगा। इसमें युवाओं और महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। अक्टूबर में एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर होने जा रहा है। शिविर में महात्मा गांधी के सहिष्णुता और बाबा साहेब अंबेडकर के सामाजिक न्याय, लोहिया के संघर्ष पर चिंतन किया जाएगा। इसमें करीब 500 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। डॉ सचान की मानें तो अखिलेश यादव इस प्रशिक्षण शिविर में आएंगे और गंगा आरती में भी शामिल होंगे। बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे



डॉ सत्यनारायण सचान को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया है। उनकी जगह अब शंभू प्रसाद पोखरियाल पर पार्टी ने विश्वास जताते हुए उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है। उनका कहना है कि पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया था और एक महीने के भीतर नई कार्यकारिणी का गठन कर लिया जाएगा। जो लोग नाराज होंगे, उनसे वार्ता की जाएगी, ताकि उन्हें संगठन से जोड़ा जा सके।



दुग्ध मंत्री सौरभ बहुगुणा की बड़ी उपलब्धि, हल्द्वानी में जल्द बनेगा दुग्ध विकास विभाग का निदेशालय

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 12 सितंबर। धामी सरकार के युवा कैबिनेट मंत्री और सितारगंज से

विधायक सौरभ बहुगुणा के नाम जल्द एक बड़ी उपलब्धि शामिल हो जाएगी। मंत्री सौरभ ने पहले चीनी मिलों की पुरानी हो चुकी दशा और घिसीपिटी व्यवस्था को

आधुनिकता की पटरी पर लाने के लिए मोडर्निजेशन पर फोकस किया और अब डेयरी, दुग्ध और पशुपालन के क्षेत्र में दूरगामी फैसलों से इस बड़े क्षेत्र की



कायाकल्प करने में जुटे हैं।

सूत्रों की माने तो लंबी जद्दोजहद के बाद राज्य के दुग्ध विकास विभाग का निदेशालय का नया भवन हल्द्वानी में बनने जा रहा है। हल्द्वानी स्थित ओपन यूनिवर्सिटी के सामने करीब 6 करोड़ की लागत से उत्तराखंड डेयरी फेडरेशन का नया निदेशालय बनेगा। जिसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है.... एक्सपर्ट बताते हैं कि मंत्री सौरभ बहुगुणा ने प्रदेश के तमाम विभागीय अफसरों से इनपुट लेने के बाद इस विभाग से जुड़े लाखों लोगों को बेहतर सुविधा और सहूलियत देने के लिए कई निर्णय लिए हैं जिसमें ये एक अहम हिस्सा है।

उत्तराखंड डेयरी फेडरेशन के सूत्र बताते हैं कि तीन बार टेंडर किए जाने के बाद अब टेंडर प्रक्रिया में कार्यदायी संस्था ने हिस्सा लिया है। शासन द्वारा गत वर्ष ही टोकन मनी के रूप में एक करोड़ रुपये आवंटित कर दिया गया था। करीब 6 करोड़ की लागत से

बनने वाले निदेशालय में अब टेंडर प्रक्रिया संपन्न हो गई है। लिहाजा हल्द्वानी में चयनित भूमि में जल्द काम शुरू होगा। आपको यहाँ बता दें कि दुग्ध विकास विभाग के निदेशालय के स्थापित होने के साथ ही राज्य में दुग्ध उत्पादकों और दुग्ध उपभोक्ताओं के लिए बेहतर सुविधाएं हो पाएंगी...

निदेशालय का पुराना भवन काफी जर्जर हो चुका है निदेशालय के निर्माण के लिए पिछले कई सालों से कार्रवाई चल रही है। जल्द ही अब निदेशालय का काम शुरू होने जा रहा है, निदेशालय के बन जाने से एक ही छत के नीचे दुग्ध विकास से जुड़ी सभी योजनाओं के अधिकारी बैठेंगे। जहां दुग्ध उत्पादकों के साथ-साथ योजनाओं की भी लाभ मिलेगा... उम्मीद की जानी चाहिए कि मुख्यालय बन जाने से लोगों को आसानी भी होगी और अधिकारियों को योजनाओं के सञ्चालन में सहूलियत भी मिलेगी।

भविष्य में पारदर्शी एवं सुचिता पूर्ण ढंग से चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हो : मुख्यमंत्री



न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून 13 सितंबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. सन्धु को निर्देश दिये हैं कि प्रदेश में भविष्य में पारदर्शी एवं सुचिता पूर्ण ढंग से चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि योग्य युवाओं का चयन हो सके।

उन्होंने इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग तथा अन्य चयन एजेंसियों को सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाये जाने के भी निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जिन पदों के रिजल्ट घोषित कर दिये हैं किंतु संस्तुति अभी नहीं भेजी गई है उस संबंध में भी केस टू केस निर्णय लेने हेतु

मुख्य सचिव एवं सचिव कार्मिक को निर्देश दिये हैं। ऐसी परीक्षाएँ जिनमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जा चुके हैं तथा कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की गई है उनमें लोक सेवा आयोग के स्तर पर नियम संगत कार्यवाही कर चयन प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिये हैं कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो परीक्षाएँ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जानी हैं उसके लिये शीघ्र विज्ञापन निर्गत कर चयन प्रक्रिया प्रारम्भ की जाय। मुख्यमंत्री ने परीक्षा परिणाम घोषित पुलिस रैंकर्स भर्ती परीक्षा के संबंध में भी शीघ्र कार्यवाही हेतु सचिव कार्मिक को निर्देश दिये हैं।



हंस फाउंडेशन ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 11 करोड़ रुपये दिए

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 12 सितंबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हंस फाउंडेशन के संस्थापक माता मंगला जी एवं भोले जी महाराज ने भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने आपदा पीड़ितों के सहयोग के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु मुख्यमंत्री को 11 करोड़ रुपये का चेक सौंपा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हंस फाउंडेशन के संस्थापक माता मंगला जी एवं भोले जी महाराज का आभार व्यक्त करते हुए हंस फाउंडेशन द्वारा राज्य सरकार को समय-समय पर सहयोग दिया जाता है। राज्य में जब भी कोई आपदा आती है या जरूरतमंदों को कोई जरूरत होती

है, तो हंस फाउंडेशन सेवा के कार्यों में हमेशा आगे आता है।

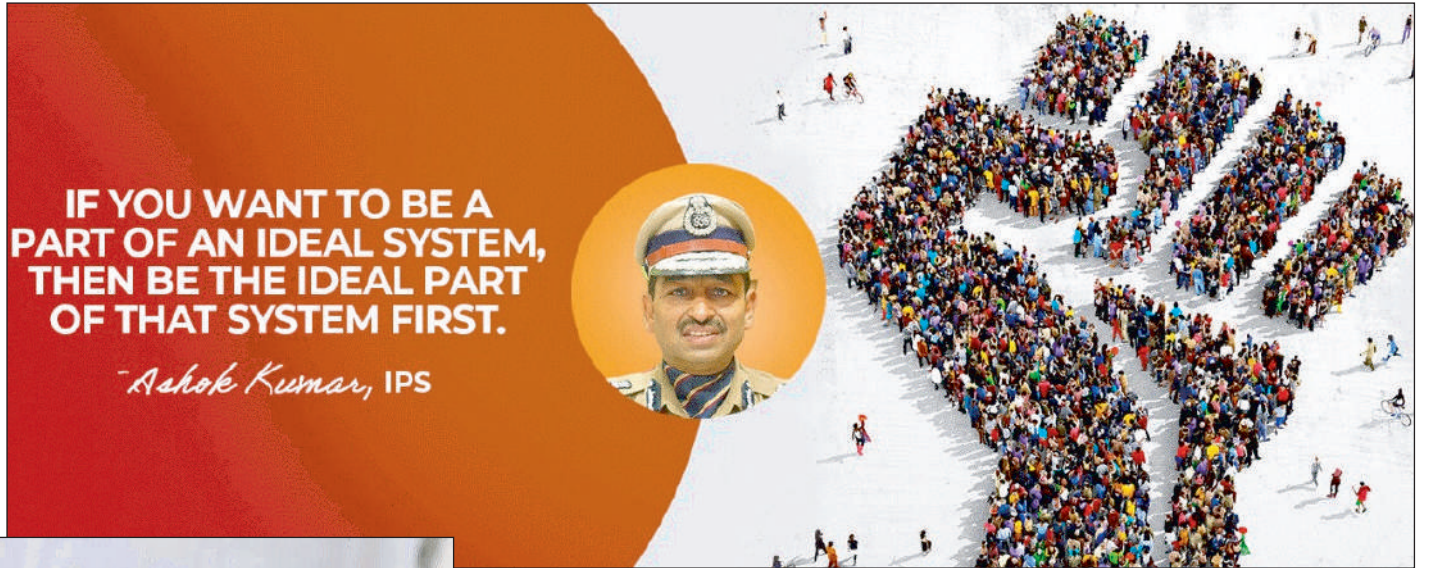
कोरोना काल में भी हंस फाउंडेशन द्वारा अनेक तरह से सेवा के कार्य किये गये। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्रों में हंस फाउंडेशन द्वारा राज्य सरकार को लगातार सहयोग दिया जा रहा है।

ड्रग फ्री स्टेट बनाने के लिए आप भी Run Against Drugs में ज़रूर दौड़िये : अशोक कुमार , डीजीपी

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

सरदार बल्लभ भाई पटेल के 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के सपने को साकार करने की प्रतिबद्धता के साथ उत्तराखंड पुलिस द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस के दृष्टिगत देहरादून मैराथन का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ हो गए हैं। आइये हम आपको बताते हैं कि इसका मकसद क्या है और आप इस प्रतियोगिता में कैसे हिस्सा ले सकते हैं।

पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार द्वारा बताया गया कि उत्तराखंड पुलिस आगामी 30 अक्टूबर 2022 रविवार को Dehradun Marathon का चौथा संस्करण आयोजित करने जा रही है जो कि अब राज्य की खेल संस्कृति का एक हिस्सा बन गई है। मुख्यमंत्री धामी के वर्ष 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि के विजन के तहत देहरादून मैराथन 2022 Run Against Drugs एवं Run For Unity के संदेश



के साथ आयोजित की जा रही है 1 पूर्व के वर्षों में भी उत्तराखंड पुलिस के द्वारा देहरादून मैराथन के तीन संस्करणों का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा चुका है।

मैराथन में पूर्व की भांति 21 KM एवं 10 KM की करायी जाएगी एवं विजेता प्रतिभागियों को कुल 10 लाख रुपये के पुरस्कार वितरित किये जाएंगे। 21 KM हाफ मैराथन में सभी प्रतिभागियों को निःशुल्क टाईमिंग चिप दी जाएगी। 21 km पूरी करने वाले समस्त प्रतिभागियों को Finishers Medals दिये जाएंगे जबकि 10 km में शीर्ष 10 प्रतिभागियों को ही Finishers Medals दिये जाएंगे। मैराथन के साथ ही Theme awareness हेतु 03 KM की एक Fun Run भी करायी जाएगी, जिसमें 14 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे प्रतिभाग कर सकते हैं।

मैराथन हेतु आयु वर्ग के हिसाब से 03 category होंगी-

1. Junior Category - 16 से 20 वर्ष आयु
2. Open Category - 20 से 45 वर्ष आयु
3. Masters Category - 45 वर्ष से अधिक आयु

For registration link

- 1) <http://ukpolicemarathon2022.in/dehradun-police-marathon-registration>
- 2) <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dehradun.policemarathon>

पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने उत्तराखंड के समस्त युवाओं को नशे के खिलाफ एकजुट एवं देश को एकता के सूत्र में पिरोने हेतु देहरादून मैराथन 2022 में प्रतिभाग करने की अपील की है। न्यूज़ वायरस भी आपसे अपील करता है कि इस सामाजिक जन जागरूकता के मिशन में अपनी हिस्सेदारी को ज़रूर सुनिश्चित कीजिये और अपनी सरकार के मिशन को सफल बनाइयें।

सड़क पर दौड़े धरती के भगवान को सलाम

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट, 13 सितंबर, मरीज के लिए डॉक्टर को भगवान यूं ही नहीं कहा जाता है। लेकिन जब डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए कुछ ऐसा कर गुजरे कि वो नज़ीर बन जाए तो जाहिर सी बात है कि वह बधाई का पात्र है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बेंगलुरु के डॉक्टर गोविंद नंदकुमार ने। दरअसल सर्जरी के लिए जा रहे डॉक्टर की कार भीषण ट्रैफिक में फंस गई थी। बीती 30 अगस्त को मणिपाल अस्पताल के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी सर्जन डॉ गोविंद नंदकुमार सरजापुर-मराठाहल्ली खंड में कार से बीच ट्रैफिक में फंस गए। इस दौरान वे पहले से तय पिताशाय की थैली की सर्जरी करने के लिए जा रहे थे। इसके बाद डॉक्टर ने बिना परवाह किए ही बीच ट्रैफिक के बीच पैदल ही दौड़ लगा दी।



दूरी 3 किमी., 45 मिनट तक लगाई दौड़ डॉक्टर गोविंद नंदकुमार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कार छोड़कर दौड़ लगानी

शुरू कर दी कि उनका पहला मरीज पहले से ही सर्जरी के लिए तैयार था। इसके साथ ही कुछ अन्य मरीज भी थे जो कि सर्जरी के बाद में उनका इंतजार कर रहे थे। नंदकुमार बीच ट्रैफिक के बीच अपनी कार से बाहर निकले और करीब 3 किमी दूर अस्पताल पहुंचने के लिए पैदल दौड़ लगाना शुरू कर दिया।

रमुझे कनिंघम रोड से सरजापुर के मणिपाल अस्पताल पहुंचना था। भारी बारिश और जलभराव के कारण, अस्पताल से कुछ किलोमीटर आगे यातायात का पूरी तरह से ठप था। यातायात सुगम होने का कोई संकेत न मिलने पर, मैं अपनी कार से बाहर निकला और अपने मरीज को देखने के लिए अस्पताल पहुंचने तक लगभग 45 मिनट तक दौड़ लगाई। उन्होंने कहा कि मैं ट्रैफिक खत्म होने के इंतजार में और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरे मरीजों को सर्जरी खत्म होने तक भोजन करने की इजाजत नहीं है। मैं उन्हें लंबे समय तक इंतजार नहीं कराना चाहता था।



देश में बिना सोचे-समझे दवा ले रहे लोग, एक साल में 500 करोड़

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट, 13 सितंबर। कोरोना महामारी की शुरुआत से ही भारत में एंटीबायोटिक दवाओं की खरीदारी काफी बढ़ गई थी। हालांकि, इसके पहले भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित एक हालिया स्टडी के मुताबिक, 2019 में देश में 500 करोड़ एंटीबायोटिक टैबलेट्स कंज्यूम की गईं। इनमें से कई दवाएं ऐसी हैं, जिन्हें ड्रग कंट्रोलर से मंजूरी भी नहीं मिली है।

ऐसे हुई रिसर्च

रिसर्चर्स ने प्राइवेट सेक्टर के ड्रग सेल्स डेटाबेस PharmaTrac के डेटा को एनालाइज किया। यह डेटा 9 हजार विक्रेताओं से इकट्ठा किया गया था। इसके बाद एक्सपर्ट्स ने कई श्रेणियों में

एंटीबायोटिक दवाओं की प्रति व्यक्ति निजी क्षेत्र की खपत की गणना करने के लिए डिफाइनड डेली डोज (DDD) मेट्रिक्स का इस्तेमाल किया। किसी भी ड्रग को कंज्यूम करने के लिए उसकी एक औसत डोज तय की जाती है, जिसे DDD कहते हैं।

एजिथ्रोमाइसिन सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा

रिसर्च के नतीजे बताते हैं कि 2019 में 500 करोड़ DDD कंज्यूम की गईं। यह हर दिन प्रति 1,000 लोगों पर 10.4 DDD के बराबर है। वैज्ञानिकों की मानें तो देश में सबसे ज्यादा एजिथ्रोमाइसिन 500 mg की गोली खाई जाती है। एक साल में 7.6% लोगों ने इसे कंज्यूम किया। वहीं, सेफिक्सिम 200 mg टैबलेट 6.5% के साथ दूसरे नंबर पर है।





शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को भारत रत्न मिले : संत समाज

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून 12 सितंबर। जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन हो जाने के बाद हरिद्वार में जगह जगह साधु संतों द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान हरिद्वार के साधु संतों ने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को भारत सरकार से भारत रत्न देने की मांग की। साथ ही उनके नाम पर जौलीग्रंट एयरपोर्ट का नाम बदलने के साथ ही देश में राष्ट्रीय शोक घोषित करने की भी मांग की गई। हरिद्वार के कनखल स्थित शंकराचार्य मठ में आयोजित शोक सभा में संतों ने शंकराचार्य की विद्वता और सरल स्वभाव का जिक्र करते हुए कहा कि स्वामी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाना चाहिए। संतों ने केंद्र सरकार से उनकी जीवन यात्रा पूरी होने पर राष्ट्रीय शोक और उत्तराखंड के देहरादून में स्थित हवाई अड्डे का नाम भी शंकराचार्य हवाई अड्डा करने की मांग की।

चार जिलों में 20 नए संक्रमित मिले, 258 पहुंची सक्रिय मरीजों की संख्या



देहरादून 12 सितंबर। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफतार थम गई है। बीते 24 घंटे के भीतर प्रदेश के चार जिलों में 20 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। सोमवार को एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। जबकि 38 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं, सक्रिय मरीजों की संख्या भी घट रही है। फिलहाल प्रदेश में 258 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। जबकि रविवार को प्रदेश में 279 सक्रिय मरीज थे।

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सोमवार को 1271 सैंपलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। वहीं, सामने आए 20 मामलों में देहरादून में आठ, हरिद्वार और पौड़ी में तीन-तीन व नैनीताल में छह संक्रमित मरीज शामिल हैं।

चंपावत के एसडीएम सदर अनिल चन्याल लापता, तलाश में जुटी पुलिस की तीन टीमें



कार्यालय पहुंचकर पूरी जानकारी ली लेकिन कोई पता न चला। इसके बाद डीएम के निर्देश पर एसडीएम कार्यालय में तैनात पीआरडी जवान रमेश कुमार ने कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

एसडीएम चन्याल 10 सितंबर को पंत जयंती के कार्यक्रम में मौजूद थे लेकिन उसी दिन दोपहर बाद से उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। 10 सितंबर को महीने का दूसरा शनिवार और रविवार अवकाश होने से कार्यालय भी बंद थे। इसलिए अभी यह भी स्पष्ट नहीं हो सका है कि वे यहां से कब और कहाँ गए। चन्याल चंपावत में सितंबर 2021 से तैनात हैं। पांच साल पहले भी वह टनकपुर और पाटी में इसी पद पर रह चुके हैं।

एसडीएम चन्याल सोशल मीडिया में खासे सक्रिय रहते हैं उनकी आखिरी फेसबुक पोस्ट नौ सितंबर को साढ़े नौ बजे की है। इसमें उन्होंने लिखा है ट्रैकिंग एंड लॉग ड्राइवर इज ऑलसो ए पीस ऑफ माइंड...।

कोतवाली में एसडीएम की गुमशुदगी की तहरीर देने वाले पीआरडी जवान रमेश कुमार ने एसडीएम के आवास पर ताला देखा था। इसकी जानकारी उन्होंने एसडीएम कार्यालय के अन्य कर्मियों को दी लेकिन रमेश कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। बस इतना कहते हैं कि 10 सितंबर को दोपहर के बाद से वह अपने घर चले गए थे और सोमवार सुबह आने पर एसडीएम आवास में ताला लटका देखा।

एसडीएम अनिल चन्याल के रहस्यमय ढंग से गायब होने से कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि एक जिम्मेदार प्रशासनिक अफसर को इस तरह का व्यवहार करना पड़ा। काम की अधिकता की वजह से मानसिक शांति का जिक्र उनकी एक फेसबुक पोस्ट में झलकता है।

सितंबर 2021 से चंपावत जिले में तैनात चन्याल ने 15 दिन के अवकाश के लिए आवेदन किया था लेकिन उन्हें तत्काल छुट्टी नहीं मिली।

चंपावत, 13 सितंबर। उत्तराखंड में चंपावत सदर के एसडीएम अनिल चन्याल रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। आवास और कार्यालय में मौजूद न होने के कारण प्रशासन की ओर से सोमवार शाम कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज करा दी गई है। पुलिस और प्रशासन की तीन टीमों उनकी खोजबीन में जुटी हैं। बताया जा रहा है कि एसडीएम ने 15 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन किया था लेकिन उनका अवकाश मंजूर नहीं हुआ था। उनके दफ्तर में एक पर्ची मिली है जिस पर लिखा हुआ है, 'मेरा सरकारी फोन जमा कर दें'।

पिथौरागढ़ जिले के गणाई गंगोली के भिगड़ी गांव के मूल निवासी अनिल चन्याल यहां अकेले रहते हैं। उनका परिवार हल्द्वानी में रहता है। चन्याल सोमवार सुबह अपने कार्यालय नहीं पहुंचे। आवास में भी ताला लटका मिला। निजी और सरकारी कार भी अस्पताल परिसर में पार्क हैं। एसडीएम को कलकट्टे में स्वच्छता से संबंधित रिपोर्ट देनी थी। रिपोर्ट न मिलने के बाद डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने जानकारी ली तो एसडीएम के निजी और सरकारी दोनों मोबाइल नंबर बंद मिले।

एसडीएम कार्यालय और उसी परिसर में स्थित तहसील कार्यालय के कर्मियों को भी एसडीएम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एडीएम हेमंत कुमार वर्मा ने एसडीएम

लक्ष्य के सापेक्ष कार्य शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिये



न्यूज़ वायरस नेटवर्क

रूद्रपुर, 13 सितंबर। जिलाधिकारी युगल किशोर पन्त की अध्यक्षता में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में जनपद स्तरीय कृषि अवसंरचना निधि की एक दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न हुई। जिसमें प्रगतिशील किसानों, सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों, बैंकर्स के साथ ही जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

कार्यशाला में सम्बोधित करते हुए जिलाधिकारी युगल किशोर पन्त ने निर्देशित करते हुए कहा कि कृषि अवसंरचना निधि में जनपद के लिए लगभग 91 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था होने के कारण बजट की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि कृषि अवसंरचना निधि के अन्तर्गत 2 करोड़ रुपये की लागत तक के प्रोजेक्ट लगाने हेतु बैंक गारण्टी की भी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सहकारिता विभाग को दिये गये

लक्ष्य के सापेक्ष एक भी लक्ष्य हासिल न करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए लक्ष्य के सापेक्ष कार्य शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिये।

डीएम ने कृषि, मत्स्य, दुग्ध, पशुपालन विभाग के अधिकारियों को योजना का लाभ इच्छुक व्यक्तियों तक पहुंचाने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि योजनान्तर्गत भवन निर्माण पर कम तथा मशीनरी एवं प्रोडक्शन पर ज्यादा धनराशि व्यय होने वाली योजनाओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाये। उन्होंने योजनान्तर्गत ऋण आवेदन पत्र रिजेक्ट करने वाले ब्रांच मैनेजर्स को पूर्ण अभिलेखों सहित सीडीओ कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये।

मुख्य कृषि अधिकारी एके वर्मा ने निधि के अन्तर्गत आने वाली पात्र परियोजनाएं की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि योजनान्तर्गत 14 बिन्दुओं यथा-जैविक आदानों का उत्पादन, जैव

उत्तेजक उत्पादन इकाइयां, नर्सरी, ऊतक संवर्धन, बीज प्रसंस्करण, कस्टम हायरिंग सेंटर, स्मार्ट और सटीक कृषि के लिए आधारभूत संरचना 8 रसद सुविधाएं-रीफर वैन और इन्सुलेटेड वाहन, परख इकाइयों के साथ ही ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म सहित 10 आपूर्ति श्रृंखला सेवाएं 12 कोल्ड स्टोर और कोल्ड चेन हेतु गोदाम और सिलोस, पैकेजिंग इकाइयां, प्राथमिक प्रसंस्करण गतिविधियां शामिल हैं।

कार्यशाला में मुख्य विकास अधिकारी विशाल मिश्रा, ओसी कलैक्ट्रेट अनामिका, परियोजना निदेशक हिमांशु जोशी, सहायक निदेशक मत्स्य संजय कुमार छिमवाल, मुख्य उद्यान अधिकारी भावना जोशी, एलडीएम एमएस जंगपांगी, प्रगतिशील किसान लेखराज सिंह, ठाकुर जगदीश सिंह, गुरमुख सिंह, मुख्त्यार सिंह, अरविन्द कुमार, मयंक तिवारी, रविन्दर सिंह, शकील अहमद, मनोज कुमार, परमजीत कौर आदि उपस्थित थे।

संपादकीय



टीबी का उन्मूलन

तपेदिक यानी टीबी एक गंभीर वैश्विक बीमारी है। अनुमान है कि दुनिया की एक-तिहाई आबादी टीबी के बैक्टीरिया से संक्रमित है, जिसमें केवल पांच से पंद्रह फीसदी लोग ही बीमार पड़ते हैं। शेष संक्रमितों को न तो टीबी की बीमारी होती है और न ही उनके जरिये यह संक्रमण दूसरों में फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, 2020 में दुनियाभर में लगभग एक करोड़ लोग तपेदिक के शिकार हुए थे और 15 लाख लोगों की मौत हो गयी थी। साल 2019 में भारत में 24 लाख से अधिक मरीजों की तादाद दर्ज की गयी थी। इस हिसाब से देखें, तो भारत में टीबी के सर्वाधिक रोगी हैं। बीमार व्यक्ति से इसका संक्रमण फैलने का खतरा भी रहता है। इस बीमारी से मुक्ति के प्रयास वर्षों से हो रहे हैं। इस क्रम में भारत सरकार ने एक विशेष कार्यक्रम 'प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान' की शुरुआत की है। इसके तहत 2025 तक देश को टीबी से पूरी तरह छुटकारा दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अभियान का शुभारंभ करते हुए इसमें शामिल होने के लिए पूरे देश का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि जब जनहित में कोई कल्याणकारी योजना बनायी जाती है, तो उसकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। टीबी और इसके निदान से संबंधित जानकारी देने के लिए एक विशेष वेबसाइट 'नि-क्षय मित्र' बनायी गयी है। राष्ट्रपति मुर्मू ने निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों, उद्योग जगत, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा नागरिकों से निवेदन किया है कि वे इस पहल में दान करें ताकि रोगियों को सफल उपचार मुहैया कराया जा सके। उल्लेखनीय है कि 2017 में एक राष्ट्रीय रणनीति तैयार की गयी थी, जिसके तहत 2025 तक इस खतरनाक बीमारी से मुक्ति का लक्ष्य तय किया गया था। इस प्रयास में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को भी सशक्त बनाया गया है। अनेक दशकों की कोशिशों तथा हाल के वर्षों में अधिक ध्यान दिये जाने से इस मोर्चे पर लगातार उपलब्धियां हासिल हुई हैं। सरकारी चिकित्सा केंद्रों पर टीबी का इलाज निशुल्क होता है। यह बीमारी असाध्य नहीं है और इसका उपचार संभव है। महामहिम राष्ट्रपति ने उचित ही रेखांकित किया है कि इसके बारे में अधिक जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। कई बार लोग टीबी के लक्षणों को सामान्य स्वास्थ्य समस्या मानकर उनकी अनदेखी कर देते हैं। ऐसे में संक्रमण के बढ़ने और फैलने का खतरा पैदा हो जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और आयुष्मान भारत जैसी अनेक पहलों से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी नीतियों और योजनाओं के केंद्र में नागरिकों को रखने से इनका प्रभाव भी संतोषजनक है। आशा है कि हमारा देश कुछ वर्षों में तपेदिक के साये से बाहर निकल जायेगा।

हरिद्वार जहरीली शराब कांड : दो और ग्रामीणों ने तोड़ा दम, सगे भाइयों की मौत

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

हरिद्वार, 12 सितम्बर। हरिद्वार पथरी की जहरीली शराब कांड में अस्पताल में भर्ती सूखा सिंह (40) और देवेन्द्र (38) की आज सोमवार सुबह मौत हो गई। दोनों को रविवार को भर्ती कराया गया था। शराब पीने से अब तक 12 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। सूखा सिंह शराब पीने से मरने वाले इशमपाल का ही भाई था। इशमपाल की शुक्रवार को शराब पीने से मौत हो गई थी। एक परिवार में जहरीली शराब से दो लोगों की मौत हो गई।

पथरी थाना क्षेत्र की शिवगढ़ ग्राम पंचायत में जहरीली शराब पीने से रविवार को तीन और ग्रामीणों की मौत हो गई। शराब पीने से बीमार हुए दो ग्रामीणों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

इनमें से एक सूखा सिंह की हालत नाजुक थी, जिसकी सोमवार को मौत हो गई। वहीं दोपहर में देवेन्द्र (38) ने दम तोड़ दिया। जहरीली शराब पीने से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि रविवार को दो लोगों की मौत ही शराब पीने से हुई है।

पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों की ओर से कच्ची शराब बांटी जा रही है। ऐथेनॉल की



अत्यधिक मात्रा होने से शराब जहरीली है। शराब पीने से शिवगढ़ ग्राम पंचायत के फूलगढ़ और शिवगढ़ गांव में शुक्रवार को दो व शनिवार को पांच लोगों की मौत हो गई थी। चार ग्रामीणों को खून की उल्टियां होने से शनिवार रात और रविवार सुबह अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। रविवार सुबह तीन बजे रूप सिंह (35) पुत्र सोम सिंह निवासी शिवगढ़ को खून की उल्टी हुई और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सुबह दस बजे रूप सिंह की मौत

हो गई। अजय पुत्र जोगेंद्र निवासी फूलगढ़, करण पाल पुत्र नितर सिंह निवासी फूलगढ़ और सूखा सिंह निवासी शिवगढ़ को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर सूखा सिंह को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सूखा सिंह जहरीली शराब पीने से जान गंवा चुके इशमपाल सिंह का भाई है। इन सभी को खून की उल्टियां हुईं और शुक्रवार को सभी ने ग्राम प्रधान प्रत्याशी की पति की ओर से बांटी गई शराब पी थी।

वाराणसी कोर्ट ने 10 मिनट में सुनाया 26 पन्नों में लिखा फैसला



एजेंसी

वाराणसी, 12 सितंबर। ज्ञानवापी-शृंगार गौरी प्रकरण में राखी सिंह समेत पांच महिलाओं की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी। जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने सोमवार को यह आदेश देते हुए प्रतिवादी अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद की ओर से दाखिल मुकदमे की पोषणीयता (मुकदमा सुनवाई योग्य है या नहीं) का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

मुकदमे की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। उस दिन मूल मुकदमे पर प्रतिवादी को जवाब दाखिल करने का मौका मिलेगा। साथ ही मुकदमे में पक्षकार बनने के लिए दिए गए प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई होगी। अब ज्ञानवापी परिसर में हुए सर्वे और वीडियोग्राफी पर भी सुनवाई होगी, जिसमें मंदिर पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा किया था और मस्जिद पक्ष ने उसे फव्वारा बताया था। इसके अलावा मस्जिद के कुछ हिस्सों में सर्वे की कार्यवाही नहीं हो सकी थी। वादी पक्ष ने दोबारा सर्वे कराने की याचिका भी दी है।

मामले में वादी के साथ ही प्रतिवादियों की ओर से दलीलें पूरी होने के बाद सभी को अदालत के आदेश का इंतजार था। दोपहर दो बजे से पहले ही वादी पक्ष के वकील और मंदिर पक्ष की महिलाएं अदालत में पहुंच गई थीं।



मस्जिद पक्ष के वकील भी आ गए थे। सुनवाई शुरू होते ही जिला जज ने पहले से तैयार 26 पन्ने के आदेश के मुख्य बिंदुओं को बताना शुरू किया। मुकदमा सुनने योग्य नहीं है, इसके लिए प्रतिवादी पक्ष ने तीन आधार दिए थे। उनकी दलील थी कि यह मुकदमा उपासना स्थल कानून 1991, काशी विश्वनाथ कानून 1983 व वक्फ कानून से बाधित है। मगर

अदालत ने इसे खारिज करते हुए कहा कि मुकदमा न तो उपासना स्थल कानून का उल्लंघन है और न वक्फ कानून का और इसलिए सुनने योग्य है।

अदालत ने दस मिनट की कार्यवाही में निर्णय सुना दिया। इस दौरान 62 लोग अदालत में उपस्थित थे। अदालत के आदेश पर प्रतिवादी अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के वकीलों ने नाखुशी जाहिर करते हुए इसे चुनौती देने की बात कही है। अंजुमन इंतेजामिया हालांकि मामले में पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। तब सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रविकुमार दिवाकर की ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की कार्यवाही के आदेश का विरोध किया गया था। यह आपत्ति हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी।

इसके बाद सर्वे में ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिलने के मंदिर पक्ष के दावे और शिवलिंग मिलने के स्थान को सील करने के स्थानीय कोर्ट के आदेश के खिलाफ इंतेजामिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई जिजा जज की अदालत को ट्रांसफर करने के साथ निर्देश दिया था कि सबसे पहले यह मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं, इस पर विचार किया जाए।

शिक्षा विभाग में रिक्त पदों की शीघ्र होगी डीपीसी : डॉ० धन सिंह रावत

कैबिनेट में लाई जायेगी डायट एवं आवासीय विद्यालयों की पृथक नियमावली

आशीष तिवारी की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 12 सितम्बर। सूबे में विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत लंबे समय से रिक्त प्रशासनिक पदों पर शीघ्र डीपीसी की जायेगी। साथ ही ब्लॉक स्तर पर रिक्त खंड शिक्षा अधिकारियों के पदों भी भरा जायेगा। राज्य के आवासीय विद्यालयों एवं

डायट के लिये पृथक नियमावली एवं कैडर बनाया जायेगा। इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्यों के 50 फीसदी पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने संबंधी नियमावली तैयार करते वक्त सभी शिक्षक संगठनों से सुझाव लिये जायेंगे, किसी भी संवर्ग के साथ अन्याय नहीं होने दिया जायेगा। इस संबंध में महानिदेशक एवं निदेशक विद्यालयी शिक्षा को शिक्षक एवं प्रधानाचार्य संगठनों को बुलाकर वार्ता करने तथा सुझाव लेने के निर्देश दे दिये गये हैं।

विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ० धन सिंह रावत ने शिक्षा महानिदेशालय ननूरखेड़ा में विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने विभाग में लंबे समय से रिक्त प्रशासनिक संवर्ग के विभिन्न श्रेणी के पदों पर डीपीसी करा कर पदोन्नति से भरने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि सूबे के जिन विकास खंडों में खंड शिक्षा

अधिकारी के पद रिक्त हैं या प्रभारी व्यवस्था की गई है। वहां पर तत्काल खंड शिक्षा अधिकारियों की तैनाती की जाय। इसके अलावा जनपद स्तर पर भी अधिकारियों की प्रभारी व्यवस्था समाप्त करते हुये प्रशासनिक आधार पर अधिकारियों की स्थाई तैनाती के निर्देश विभागीय सचिव को दिये।

डॉ० रावत ने आगामी कैबिनेट बैठक में विद्यालयी शिक्षा परिषद में दो विषयों में अनुत्तीण छात्रों को अंक सुधार परीक्षा का मौका दिये जाने तथा डायट एवं आवासीय विद्यालयों के पृथक नियमावली एवं कैडर का प्रस्ताव लाने के निर्देश दिये। हाल ही कैबिनेट द्वारा प्रधानाचार्य के 50 फीसदी पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने के निर्णय को सभी के हित में बताते हुये उन्होंने बताया कि नियमावली तैयार करते समय शिक्षक एवं प्रधानाचार्य संगठनों के पदाधिकारियों से वार्ता कर उनके सुझाव भी शामिल किये जायेंगे। इसके लिये उन्होंने महानिदेशक एवं निदेशक विद्यालयी शिक्षा को शीघ्र बैठक करने के निर्देश दे दिये हैं। विभागीय मंत्री ने पीएम-श्री योजना के अंतर्गत प्रत्येक विकासखंड में विद्यालयों का चयन करने का निर्देश भी विभागीय अधिकारियों को दिये।



बैठक में सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ सिंह, महानिदेशक बंशीधर तिवारी, निदेशक गवर्नाल, अनु सचिव विभूति रंजन सहित रमन, अपर सचिव योगेन्द्र यादव, दिप्ती आर०के० कुवार, सीमा जौनसारी, वंदना अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

बीईओ के रिक्त पदों पर शीघ्र तैनाती के निर्देश

उत्तराखंड में डेंगू के मरीजों की संख्या 300 पार, प्रतिदिन मिल रहे संक्रमित, अब रोकथाम की चुनौती



न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 12 सितम्बर। उत्तराखंड में डेंगू मरीजों का आंकड़ा तीन सौ पार पहुंच गया है। प्रतिदिन डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में इसके रोकथाम की चुनौती बनी हुई है।

सोमवार को देहरादून और पौड़ी जिले में डेंगू के 10 मरीज मिले हैं। नवंबर तक डेंगू संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। अब तक प्रदेश के पांच जिलों में कुल 324 मरीज डेंगू से ग्रसित मिले। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरोना से ज्यादा डेंगू के रोकथाम की चुनौती है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू से बचाव व रोकथाम के लिए सभी जिलों को कड़ी निगरानी,

लार्वा खत्म करने के लिए कीटनाशक छिड़काव व फॉगिंग के निर्देश दिए गए हैं।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी जिलों से प्रतिदिन बचाव व रोकथाम संबंधित रिपोर्ट भी ली जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक देहरादून जिले में 128, हरिद्वार में 117, पौड़ी में 54, टिहरी में 20, नैनीताल में आठ डेंगू के मामले सामने आए हैं।

प्रभारी सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार का कहना है कि डेंगू से बचाव व रोकथाम की राज्य स्तर से निगरानी की जा रही है। सभी सीएमओ को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में गहन निगरानी कर एलाइजा जांच की जाए।

जीबी पंत संस्थान घुड़दौड़ी के पूर्व कुलसचिव को एसआईटी ने किया गिरफ्तार

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 12 सितम्बर। उत्तराखंड के पौड़ी में जीबी पंत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान घुड़दौड़ी के पूर्व कुलसचिव संदीप कुमार को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व कुलसचिव पर पद पर रहते हुए अवैध तरीके से नियुक्तियां करने, निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितता, मैस के लिए बर्तनों की खरीद में अनियमितता सहित कई आरोप हैं। एसआईटी ने पूर्व कुलसचिव को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। अदालत के आदेश पर संदीप कुमार को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

जीबी पंत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान घुड़दौड़ी के पूर्व कुलसचिव संदीप कुमार को तत्कालीन प्राचार्य डा. एमएल देवल ने सितंबर 2005 में बिना पद की स्वीकृति के

टीपीओ (ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर) के पद पर नियुक्ति प्रदान की थी। इस पद को शासन ने वर्ष 2008 में स्वीकृति दी थी। संदीप को अगस्त 2016 में सबसे पहले संस्थान में कुलसचिव का प्रभार सौंपा गया था। दिसंबर में उनसे जिम्मेदारी वापस ले ली गई थी, लेकिन दो सप्ताह बाद ही उन्हें दोबारा कुलसचिव का प्रभार सौंप दिया गया था।

वर्ष 2017 में प्रभारी कुलसचिव की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए क्षेत्रीय युवाओं ने आंदोलन किया था जिसके बाद तत्कालीन डीएम सुशील कुमार ने नवंबर 2017 में संदीप से कुलसचिव का प्रभार छीन लिया था। जून 2018 में संदीप की कुलसचिव पद पर नियमित नियुक्ति हुई थी, लेकिन बीओजी (बोर्ड ऑफ गवर्नेंस) ने तैनाती पर रोक लगा दी थी। दिसंबर 2019 को संदीप कुमार ने कुलसचिव का पदभार संभाला

था। इस बीच संस्थान में भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता, नियुक्तियों में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए क्षेत्रीय ग्रामीणों व संस्थान के कर्मचारी संगठन ने आंदोलन की चेतावनी दी। साथ ही कई स्तरों पर संदीप कुमार की शिकायत भी की गई थी। इसके बाद अगस्त 2021 में संदीप कुमार को कुलसचिव के पद से हटा दिया था। सितंबर 2021 में उन्हें निलंबित किया गया और विगत 14 मई 2022 को बीओजी में संदीप की कुलसचिव के पद से सेवा समाप्त कर दी गई थी। जून माह में उनके टीपीओ पद पर नियुक्ति को लेकर भी जांच शुरू हुई चल रही है। एसएसपी यशवंत सिंह चौहान ने बताया कि जीबी पंत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान घुड़दौड़ी के पूर्व कुलसचिव संदीप कुमार को एसआईटी ने देहरादून से गिरफ्तार किया। कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी की अदालत के आदेश पर संदीप

को जिला कारागार खांड्यूसैण जेल भेज दिया है।

घुड़दौड़ी के पूर्व कुलसचिव संदीप कुमार पर वर्ष 2018 में कुलसचिव, 2019 में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के 44 पदों पर अवैध तरीके से नियुक्तियां करने, टीक्यूप फंड से 2 करोड़ के लेन-देन, निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितता, मैस के लिए बर्तनों की खरीद में अनियमितता के आरोप हैं। इसके अलावा संदीप कुमार ने कुलसचिव के पद से निलंबित होने से पहले 10 लाख संस्थान से लिए थे जिसे अभी तक समायोजित नहीं किया गया है। संस्थान के तत्कालीन प्रभारी कुलसचिव डा. संजीव नैथानी ने 30 अक्टूबर 2021 को पूर्व कुलसचिव के खिलाफ संस्थान के दस्तावेज गायब किए जाने सहित कई आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी थी। मामले में पूर्व कुलसचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

दैनिक
न्यूज़ वायरस

न्यूज़ वायरस नेटवर्क प्रा. लिमिटेड, मेरठ के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक मौ. सलीम सैफी द्वारा विश्वनाथ प्रिंटेर्स, अजबपुर कलां, देहरादून से मुद्रित एवं 48/3 बलबीर रोड, डालनवाला, देहरादून (उत्तराखंड) से प्रकाशित।

सम्पादक :

मौ. सलीम सैफी
कार्यकारी सम्पादक
आशीष तिवारी

दूरभाष : 0135-2672002

email-dainiknewsvirus@gmail.com

RNI No.-UTTHIN/2012/44094

वाद-विवाद का न्याय क्षेत्र देहरादून न्यायालय मान्य होगा